

दिनांक 5-9-1982

माननीय रेल मंत्रीजी,
भारत शासन
नई दिल्ली

विषय : रतलाम से डूंगरपुर-राजस्थान-व्याया बांसवाड़ा
तथा बांसवाड़ा से बड़ी सादड़ी रेल लाइन का
सर्वे कराने बाबद ।

CCCCCCCCCCCC

मान्यवर महोदय,

कुछ वर्षों पूर्व रतलाम से बांसवाड़ा रेल लाइन बिछाने हेतु आपके मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने सर्वे किया था किन्तु तब वह लाइन डालना लाभप्रद नहीं समझा गया था । मेरा सुझाव है कि रतलाम-डूंगरपुर-बड़ी सादड़ी व्याया बांसवाड़ा लाइन डालना अब लाभप्रद रहेगा । गुजरात के पूर्वी-उत्तरी क्षेत्र में देश का एक बहुत बड़ा आदिवासी वर्ग निवास करता है । इस क्षेत्र में अपार मात्रा में खनिज पदार्थ उपलब्ध है । सीमेन्ट की अनेक फेक्ट्रीयां यहाँ पर खुल रही हैं । बांसवाड़ा के समीप माही बजाज सागर बांध बन जाने से इस क्षेत्र की उन्नति के द्वारा खुल गये हैं जिसमें रेल विभाग भी योगदान दे दे तो औद्योगिकरण को गति मिल सकेगी तथा एक पिछड़े हिस्से का विकास का जो वैधानिक अधिकार है वह तक मिल सकेगा ।


.....2

(11)

फिलहाल गुजरात एवं राजस्थान के कुछ इलाकों में माल पहुंचाने हेतु लंबी यात्रा करनी पड़ती है परन्तु इस रेल लाइन के डल जाने से अजमेर-खण्डवा सेक्शन व रतलाम-बड़ौदा-अहमदाबाद से सेक्शन पर से भी अनावश्यक भार में कमी हो सकेगी ।

अतः बजाय रेल मार्गों के तिहरीकरण करने के इस प्रकार की आउट-एजेंसियों को मूर्तस्म दिया जाना चाहिये और नये रेल मार्ग डालकर यातायात को हल्का किया जाना चाहिये ।

भवदीय


॥ अनिल कुमार झालानी ॥

प्रति,
श्री कांतिलाल भूरियाजी
कैबिनेट मंत्री जनजातीय मामले
भारत शासन
दिल्ली

ज्ञापन

22.6.09

विषय :- रतलाम-बांसवाड़ा- डुंगरपुर रेल लाईन हेतु ।

माननीय,

रतलाम-बांसवाड़ा तथा डुंगरपुर क्षेत्र से गत करीब 50-60 वर्षों से एक मांग उठती रही है और वह है रतलाम-बांसवाड़ा-डुंगरपुर रेल लाइन की मांग। संलग्न समाचार पत्रों की कतरनों को देखे तो आश्चर्य होगा कि 10 नवंबर 1956 के नईदुनिया में प्रकाशित एक समाचार में यह लिखा गया है कि रतलाम-बांसवाड़ा रेल लाइन का सर्वे पश्चिमी रेलवे के इंजीनियर श्री गुरुदासराम कर रहे हैं तथा उन्होंने अब तक बीस मिल का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। इसी तरह 9 अप्रैल 1958 को प्रकाशित नईदुनिया के अनुसार इंदौर-रतलाम-डुंगरपुर नवीन रेललाइन की योजना स्वीकृत हो चुकी है तथा आगामी वर्ष में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

अत्यंत हैरानी की बात है कि लगभग 60 वर्ष पूर्व जिस योजना के स्वीकृत होने एवं कार्य प्रारंभ होने की खबरें प्रकाशित हुई उस पर आज तक कोई काम शुरू नहीं हो सका। आदिवासी क्षेत्रों को रेल सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से एवं पश्चिमी म.प्र. व राजस्थान को रेलमार्ग से जोड़ने के लिए रतलाम-बांसवाड़ा-डुंगरपुर रेल लाइन वरदान साबित होगी। इसी के साथ वेस्टर्न कारीडोर से मिलने वाले व्यावसायिक लाभ भी इस महत्वपूर्ण रेलमार्ग के माध्यम से राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचाए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इस रेल परियोजना के लिए गत बजट में तत्कालीन रेलमंत्री लालूप्रसाद यादव ने भी प्रावधान किया था। किंतु दुर्भाग्य से इस क्षेत्र के लिए स्वीकृत उक्त योजना पर अब तक कोई कार्य शुरू नहीं हो सका है। यह मांग समय-समय पर उठती रही है और केंद्रीय रेल

मंत्रालय ने इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत करते हुए हमेशा कार्य प्रारंभ करने की बात की है। आपसे अनुरोध है कि आप इस समूचे क्षेत्र को रेल सुविधा का लाभ दिलवाने के लिए इस मुद्दे को बजट के पूर्व प्रभावी रूप से उठाए और आगामी बजट में इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत कराए ताकि करीब छह दशक पुरानी यह मांग पूरी की जा सके।

धन्यवाद

दिनांक 22.06.2009

भवदीय

(अनिल झालानी)

सामाजिक कार्यकर्ता, रतलाम

8.2.1960

की नई दुनिया से

■ त्रिवेन्द्रम

केरल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री आर. शंकर ने प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के बाद कहा कि सामान्यतः सदस्यों ने संयुक्त सरकार के पक्ष में ही राय व्यक्त की है। कांग्रेस द्वारा एकदलीय सरकार यदि वह संभव भी है तो सदस्यों ने इसके पक्ष में राय व्यक्त नहीं की है। श्री शंकर ने कहा कि कार्यसमिति ने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। अंतिम निर्णय कांग्रेस संसदीय बोर्ड के लिए छोड़ दिया गया है।

■ इलाहाबाद

कल अपराह्न इलाहाबाद के अर्द्धकुंभ मेले के एक भाग में भीषण अग्निकांड के परिणामस्वरूप 96 झोपड़ियाँ जल गई हैं और आग से 8 व्यक्तियों को चोटें आईं, जिनमें 2 महिलाएँ भी हैं।

■ शीर्षक संचय

रतलाम - बाँसवाड़ा रेलवे लाइन बनने की संभावना : रेलमंत्री द्वारा वस्तुस्थिति का निरीक्षण।

नई दिल्ली : आज से संसद का बजट अधिवेशन आरंभ : रेलवे बजट 17 फरवरी तथा सामान्य बजट 29 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा।

गया : सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस में दंगा : 33 घायल।

एरनाकुलम : केरल में मंत्रिमंडल निर्माण का प्रश्न : दिल्ली मोर्चे के नेताओं तथा अन्य व्यक्तियों की श्री डेबर से चर्चा।

50 साल पहले

9-4-1958 की नईदुनिया से

- * नई दिल्ली : प्रधानमंत्री पं. नेहरू ने आज लोकसभा में कहा कि जब वे तिब्बत जाएँगे तो वहाँ वे आठ या दस दिन बिताएँगे। उप-राष्ट्र मंत्री श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने कहा कि प्रधानमंत्री को चीनी सरकार ने तिब्बत यात्रा के लिए आमंत्रित किया है और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।
- * शीर्षक संचय : भोपाल में मेडिकल छात्रों के हमले की तीव्र भर्त्सना : विधानसभा में स्पीकर द्वारा तीन स्थगन प्रस्ताव अग्राह्य : मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन को दुर्घटना की जानकारी : हमले में 16 छात्र घायल एवं काफी क्षति।
- * इंदौर : रतलाम-डूंगरपुर नवीन रेलवे लाइन की योजना स्वीकार : आगामी वर्ष में ही निर्माण कार्य शुरू।

50 साल पहले

10-11-1956 की नई दुनिया से

* भोपाल : मध्य प्रदेश के कुछ शासकीय कार्यालयों को कुछ समय के लिए नागपुर में ही रखने का निश्चय किया गया है। यह निश्चय इसलिए किया गया है कि भोपाल में निवास एवं कार्यालय की तत्काल व्यवस्था होना संभव नहीं है। प्रदेश के निर्माण पर नागपुर से आए 400 कर्मचारियों में 200 वापस नागपुर चले गए हैं।

* बेलिया घाट : कांग्रेस अध्यक्ष श्री उ. न. डेबर ने भाषण देते हुए देश के नागरिकों से राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए अपने आपको समर्पित कर देने की अपील की। आपने कहा- हम हमारी पंचवर्षीय योजना के साथ आगे बढ़ने का पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं किंतु कोई नहीं कह सकता कि दुनिया की इस संकटकालीन स्थिति का उस पर क्या असर होगा।

रतलाम : रतलाम-बाँसवाड़ा पश्चिम रेलवे का सर्वे अतिरिक्त रेलवे के सर्वे इंजीनियर श्री गुरुदाससाम कर रहे हैं। आपने अभी तक 20 मील का सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया है।

अनिल झालानी

101, “देवप्रस्थ”, पावर हाउस रोड,

रतलाम (म.प्र.) 457001

☎ : 074 12 (O)270216, (R)270217

मो. 9300223310

प्रति,

माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान,
मुख्यमंत्री,
मध्य प्रदेश शासन भोपाल

9.1.2011

विषय :- रतलाम, बांसवाड़ा डूंगरपूर रेललाईन में मध्यप्रदेश का अंश स्वीकृत करने बाबत।

मान्यवर महोदय,

पश्चिमी मध्यप्रदेश तथा दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य आबादी की सुविधा के लिये गत 60 वर्षों से रतलाम, बांसवाड़ा होकर डूंगरपुर तक रेलमार्ग बिछाने की मांग होती रही है। जिसका समय-समय पर सर्वे कार्य भी हुआ है। अतंतः वर्तमान सर्वेनुमान से इसकी कुल लागत 2050 करोड़ अनुमानित की गई है।

उक्त रेलमार्ग का सबसे बड़ा लाभ राजस्थान में स्थापित होने वाले थर्मल पावर स्टेशन को कोयले की आपूर्ति की सुगमता है जिसकी स्थापना होने से मध्यप्रदेश को भी विद्युत मिल सकती है, इस संपूर्ण रेल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन करने पर 50 प्रतिशत राशि रेल्वे बोर्ड व्यय करने को सैद्धांतिक रूप से सहमत हो चुका है।

इसमें राजस्थान सरकार को जो अंश देना था वह 1050 करोड़ की स्वीकृति एवं सहमति मुख्य मंत्री श्री अशोक गेहलोत द्वारा घोषणा कर दी गई है इसी के साथ वहां की सरकार रेल्वे को रेल मार्ग की 750 हैक्टर भूमि अर्जन करके प्रदान करेगी जिसकी लागत 150 करोड़ भी वह प्रथम से वहन करने को तत्पर है।

महोदय, गत दिनों इन्दौर मनमाड़ रेललाईन हेतु भी इसी प्रकार के एक प्रस्ताव पर आपके द्वारा राज्य हित में सहर्ष म.प्र. का भाग देने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी जिसके आधार पर उक्त रेल मार्ग स्वीकृति की दिशा में अग्रसर हो रहा है।

माननीय महोदय रेल्वे का महत्वपूर्ण जंक्शन होने के कारण रेल्वे रतलाम की अर्थव्यवस्था, व्यापार व्यवसाय सबकी रीढ़ है तथा यहां के नागरिकों को जीवनयापन बहुत कष्ट इस पर निर्भर है। आसपास चहुं ओर तेजी से हो रहे विकास के कारण रतलाम पिछड़ता जा

अनिल झालानी

101, “देवप्रस्थ”, पावः हाउस रोड,

रतलाम (म.प्र.) 457001

☎ : 07412 (O)270216, (R)270217

मो. 9300223310

.2.

रहा है तथा यहां स्थापित उद्योग शनै-शनै बंद हो जाने से इसका विकास अवरूद्ध हो गया है।

विगत दिनों से इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि क्षेत्र में नये उद्योग आरंभ हों किन्तु अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है जबकि इस कमी की पूर्ति अतिरिक्त रेलवे सुविधाओं के विस्तार से संभव है और रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल परियोजना जो स्वीकृति के मुहाने पर खड़ी है, मात्र इस कारण से लंबित नहीं हो जाए कि इसमें मध्यप्रदेश राज्य ने अपना अपेक्षित सहयोग या अंश देने में समय पर रुचि नहीं दिखाई।

अतः आज ही इस पहल को आगे बढ़ाते हुए इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के विकास के लिये तथा प्रदेश के उर्जा संकट को दूर करने के मुख्य लक्ष्य को रखकर जो रेलमार्ग डालने का निमित्त बना है वह अवसर हाथ से न चला जाए, इसके लिये मध्यप्रदेश की ओर से जो भी अनुपातिक सहयोग की अपेक्षा है, इसकी सहमति की घोषणा करेंगे तो निश्चित ही इस नये रेलमार्ग के कारण संपूर्ण पूर्वी तथा दक्षिणी भारत का सम्पर्क पश्चिमी मध्यप्रदेश को मिलने से प्रदेश तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा और परियोजना से प्रदेश को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भरपूर लाभ मिल सकेगा।

धन्यवाद !

भवदीय

(अनिल झालानी)

रतलाम-डूंगरपुर रेल परियोजना हेतु आगामी रेल बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान हो

रतलाम-बांसवाडा-डूंगरपुर रेल लाईन की घोषणा आगामी रेल बजट में ही की जावे ताकि इस आदिवासी अंचल की 50-60 वर्ष पुरानी मांग शिघ्र पुरी हो सके और रतलाम के व्यापार व्यवसाय की तरक्की के द्वार भी खुल सके । यह मांग समाजसेवी अनिल झालानी ने रेल मंत्री सुश्री ममता बेनर्जी एवं क्षेत्रीय सांसद तथा केन्द्रीय मंत्री श्री भूरिया जी से की है ।

इसी मुद्दे को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान को सम्बोधित करते हुए एक पत्र नगर विधायक को श्री पारस सकलेचा को गत दिनों सौंपकर श्री सकलेचा से आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री से अपने अच्छे एवं विश्वसनीय सम्बंधों का आधार लेकर उक्त रेल परियोजना के सम्बंध में मुख्यमंत्री से चर्चा कर शिघ्र ही यह घोषणा करवाए कि प्रदेश सरकार से जो भी सहयोग अपेक्षित होगा उसकी त्वरित रूप से पूर्ति की जावेगी ताकि चालू वर्ष से ही योजना पर अमल प्रारंभ हो ।

श्री झालानी ने प्रदेश सरकार का ध्यान इस भूल की ओर भी आकृष्ट किया है कि यदि परियोजना के प्रारंभिक चरण में मध्य प्रदेश भी भागीदार बनता तो राजस्थान में स्थापित हो रहे तीनों थर्मल पॉवर स्टेशनों से प्रदेश को भी विद्युत मिल सकती थी जिसकी की कोयले की आपूर्ति भी मध्य प्रदेश से ही होना है ।

श्री झालानी ने बताया कि राजस्थान सरकार अपने प्रदेश की विद्युत प्रदाय व्यवस्था को सुधारने के लिये इस कदम उतावली है कि ना केवल आधी राशि का निर्धारित मापदण्ड की स्वीकृति दी बल्कि, रेल पथ के भू-अर्जन हेतु राशि स्वीकृत कर विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी की भी तत्काल नियुक्ति कर दी गई । यह परियोजना की सफलता के पक्ष में शुभ संकेत है ।

श्री झालानी ने यह भी इंगित किया है जहां एक ओर यह परियोजना डी.एम. आई.सी. के अन्तर्गत अति आवश्यक है वहीं दूसरी ओर रतलाम के लिये यह जीवन रेखा साबित होगी क्योंकि पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में जुड़ने और रतलाम रेल मण्डल का रतलाम में स्थाईत्व का इसके माध्यम से एक महत्वपूर्ण कारण बनेगा ।

- 1) माननीय सुश्री ममताजी बेनर्जी
रेल मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली
- 2) माननीय श्री कान्तिलालजी भूरिया
केन्द्रीय मंत्री, आदिवासी विकास, नई दिल्ली
- 3) माननीय श्री ताराचंदजी भागोरा,
संसद, बांसवाड़ा (राज.) नई दिल्ली।

2010/2013

माननीय महोदय,

आजादी के पश्चात एक ओर इस बात का जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाता रहा कि जनजातीय क्षेत्रों का विकास ही शासन व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य है, परन्तु हकीकत कुछ और बयां करती है।

इस पत्र के साथ समाचार पत्रों की कटिंग संलग्न भेज रहा हूँ। 1956 में रतलाम-बांसवाड़ा रेल लाईन का सर्वे शुरू हुआ था। 1958 को समाचार प्रकाशित होता है कि रतलाम-डुंगरपुर की रेलवे लाईन की योजना स्वीकार। 1960 रेल मंत्री द्वारा निरीक्षण भी कर लिया जाता है। बावजूद इसके 55 वर्ष गुजर जाने के बाद भी रेलवे लाईन का कोई अस्तित्व न होना, क्षेत्र की जनता की भावना के साथ सरासर खिलवाड़ है।

कही न कही इसका कारण क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों विशेषकर तत्कालीन सांसदों को इसकी जानकारी न होने से इस हेतु विशिष्ट प्रयास न करना भी रहा होगा।

दूसरी ओर उसी दौरान गुना भवसो-देवास रेल लाईन की इन्दौर क्षेत्रवासियों द्वारा (विशेषकर समाचार पत्रों के प्रयासों से) इस मार्ग को चालू हुए भी लगभग 12 वर्ष गुजर चुके हैं। जबकि इसी अवधि की रतलाम-डुंगरपुर की रेलवे लाईन अभी भी सर्वेक्षण स्तर पर ही अटकी होना यह सिद्ध करता है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जनता अभी भी अपेक्षा की शिकार

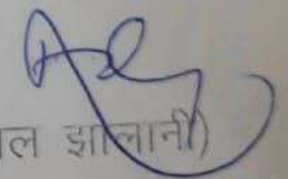
है। यदि इस आधार पर समय समय पर सरकार से आग्रह किया जाता तो यह मार्ग बहुत पहले ही शुरू हो चुका होता ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर भारत जाने के लिये बांसवाड़ा क्षेत्र की जनता को रतलाम तक सड़क मार्ग से आना जाना पड़ता है। यदि यह मार्ग बनता है तो देश के दक्षिणी एवं पूर्वी क्षेत्र से राजस्थान का सीधा सम्पर्क जुड़ जाएगा और माल सामान के लदान की बेहतर गुंजाई होने से रेलवे को अच्छा राजस्व भी मिलेगा। भविष्य में बनने जा रहे डी.एम.आई सी से लिंक होने के लिये भी इस रूट का निर्माण तत्काल आवश्यक है।

अतः निवेदन है कि रेल मंत्रालय इस योजना को आगामी रेल बजट में कम से कम 100 करोड़ का प्रवधान करके इस मार्ग की निर्माण प्रक्रिया को प्रारम्भ करना सुनिश्चित कर क्षेत्र की आदिवासी जनता के उत्थान के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रदर्शित करें।

धन्यवाद

भवदीय


(अनिल ज्ञानानी)

प्रति,

श्रीमान जिलाधीश महोदय (भूअर्जन)
द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय (भूअर्जन)
रतलाम

विषय :- भूअर्जन मुआवजे की राशि के भुगतान के अतिविलम्ब होने बाबत
संदर्भ :- रतलाम -बासवाडा-डूंगरपुर रेल-लाईन।

महोदय,

आपका ध्यान उक्त प्रस्तावित रेल लाईन की धीमी कार्य गति की और आकृष्ट करने में आता है कि उक्त परियोजना हेतु भूअर्जन का अवार्ड घोषित हुए लम्बा समय व्यतीत होने के उपरान्त भी सैकड़ों भूमिस्वामियों-कृषकों-आदिवासियों को उनकी अर्जित की जा रही भूमि के मुआवजे का भुगतान अभी तक वितरित नहीं हुआ है।

प्राप्त जानकारी अनुसार जिस वक्त भूमि अर्जित की गई थी उस वक्त के बाजार मूल्य को आधार मानते हुए भूमिया अर्जित की गई थी एवं मूल्यांकन तत्समय के बाजार मूल्य को आधार मानते हुए मुआवजा राशि तय की गई थी। ऐसे में समय व्यतीत होने से पक्षकारों को मुआवजा राशि वितरित नहीं करने के कारण उनके द्वारा ब्याज की मांग की जा सकती है। जिसके कारण वैधानिक पेचीदगियां बढ़ेगी इससे जहां अवार्ड में पुर्नगणना तथा संशोधित अवार्ड पारित कराना, बजट स्वीकृत कराना आदि कार्यवाही बढ़ेगी ओर इस कारण से परियोजना में भी विलम्ब होने से परियोजना की लागत भी बढ़ेगी।

अतः विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मुआवजा राशि को तत्काल भुगतान कराने की व्यवस्था करने की कृपा करें। ताकि इस आदिवासी अंचल को इस रेल सुविधा की शीघ्र सौगात मिल सके।

इति, दिनांक : 23/12/2015

भवदीय

अनिल झालानी

प्रतिलिपी :-

1. श्रीमान चेयरमेन एण्ड एमडी, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, जनपथ ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान
2. श्री संजय मल्होत्रा जी प्रमुख सचिव (उर्जा) राजस्थान सरकार, जयपुर राजस्थान
3. श्रीमान अभियंता, पश्चिम रेलवे (निर्माण), डीआरएम कार्यालय, रतलाम

दिनांक 18/08/2017

प्रति,

माननीय श्री ए.के. मित्तल साहब
अध्यक्ष, रेल्वे बोर्ड, नई दिल्ली।

विषय :- Western Dedicated Freight corridor से link करने हेतु
रतलाम-बासवाडा-डुंगरपूर रेल लाईन रुके के प्रोजेक्ट को पुनः आगे बढाने
हेतु निवेदन।

महोदय,

आपके ध्यान मे 'रतलाम -बासवाडा-डुंगरपूर रेल लाईन' की ओर आकृष्ट कर
रहे है जिसका कुछ वर्ष पूर्व कर कार्य आरंभ कर दिया गया था।

ऐसा ज्ञात हुआ है कि इस प्रोजेक्ट की लागत मे राजस्थान सरकार का जो अंशदान
देना था, वह वहां की राज्य सरकार अब देने से हाथ खींच रही है, और फलस्वरूप यह
प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है।

प्रस्तावित कोरिडोर की सीमाओं की परिधी रतलाम को भी शामिल किया गया है।
ऐसे मे राजस्थान के डुंगरपूर तक रेल लाईन का कनेक्शन जहां आवश्यक है वही दूसरी
ओर यह क्षेत्र कोरीडोर का भाग होने से यह रतलाम -डुंगरपूर रेल परियोजना उसकी
पूरक है तथा योजना की मांग की पूर्ति और क्षेत्रीय सम्पर्क का कार्य भी करेगा।

अतः इस ट्राईबल एरिया के विकास को भी ध्यान मे रखते हुए रतलाम -बासवाडा-
डुंगरपूर रेल प्रोजेक्ट को पुनः कार्यारम्भ किया जाने के लिये नये सिरे से पुनः प्रयास
आरम्भ होना चाहिये।

कृपया समुचित कार्यवाही करने का कृपा करें।

भवदीय

अनिल झालानी

“सृजन भारत”

(पूर्व में “भारत गौरव” अभियान)

● समस्या

● सुझाव

● समाधान

● राजनैतिक

● प्रशासनिक

● सामाजिक सुधार के लिए प्रयासरत

संयोजक

अमिल झालानी

101, “देवप्रस्थ” पावर हाऊस रोड, रतलाम 457001 (म.प्र.)

मो. 9300223310, E-mail : anilkjhalani@gmail.com

दिनांक : 19/09/2020

प्रति,

५८

माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी

प्रधानमंत्री भारत सरकार

7 रेस कोर्स रोड, नई दिल्ली

माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी

जनजाति मामलों के मंत्री भारत सरकार,

शास्त्री भवन ए विंग डॉ राजेन्द्र प्रसाद मार्ग,

नई दिल्ली।

श्री अशोक जी गेहलोत,

मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार,

सचिवालय जयपुर, राजस्थान

माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान,

मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन,

अरेरा हिल्स भोपाल।

विषय : - रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल लाइन का रूका कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि मध्य प्रदेश तथा राजस्थान पश्चिमी मध्य प्रदेश के रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र एवं दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर सागवाड़ा इत्यादि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के विकास की रेखा रतलाम से डूंगरपुर एक रेल लाइन डालने की परियोजना विगत लगभग 60-65 वर्षों से लंबित है। इस परियोजना पर उस समय कुछ वर्षों पूर्व कार्य भी प्रारंभ हो चुका था किंतु ज्ञात हुआ था की की राजस्थान सरकार के पास वित्तीय प्रबंध न होने से तत्कालीन वसुंधरा राज्य सरकार ने इसे हाथ खींचते हुए रोक दिया था। महोदय उक्त परियोजना का काफी कुछ कार्य पूर्ण हो चुका है जिसमें शासन का लंबा निवेश भी हो चुका है।

“सृजन भारत”

(पूर्व में “भारत गौरव” अभियान)

● समस्या

● सुझाव

● समाधान

● राजनैतिक

● प्रशासनिक

● सामाजिक सुधार के लिए प्रयासरत

संयोजक

अनिल झालानी

101, “देवप्रस्थ” पावर हाऊस रोड, रतलाम 457001 (म.प्र.)

मो. 9300223310, E-mail : anilkjhalani@gmail.com

यदि सरकार की मान्यता है कि आदिवासी क्षेत्रों का विकास किया जाए और आदिवासी जनता का जीवन उत्थान किया जाए तो इस क्षेत्र में रेल मार्ग बिछाना अत्यंत आवश्यक है। पर्याप्त नेतृत्व न होने के कारण ही यह लाइन लंबे समय से उपेक्षा की शिकार है। अतः एक बार पुनः आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहेंगे कि आदिवासियों के विकास की जीवन रेखा बनने वाली इस रेलमार्ग का शीघ्र अति शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए ताकि इस आदिवासी अंचल का चौमुखी विकास हो सके।

उल्लेखनीय है उक्त मार्ग डीएमआईसी योजना के अंतर्गत जो विभिन्न परियोजनाएं चल रही है उन्हें भी जोड़ने का काम करेगा।

आशा है सरकार शीघ्र ही इस पर निर्णय लेकर कार्य प्रारंभ करेंगे

धन्यवाद।

भवदीय


(अनिल झालानी)

012

दिनांक 29/09/2020

OLC

प्रति,

माननीय श्री नितीन गडकरी जी
सडक परिवहन एवं राजरानी मंत्री भारत सरकार,
ट्रासपोर्ट भवन नई दिल्ली

विषय : दिल्ली से मुंबई के लिए बनने जा रहे 8 लेन मार्ग में से गुजरने वाली प्रस्तावित 'रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल लाइन' क्रॉसिंग (संगम स्थल) पर ओवर ब्रिज का प्रावधान रखने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा एक रेल परियोजनाएं निर्माणाधीन है। वर्तमान में निर्मित हो रहे मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर रतलाम जिले के ग्राम पलसोडी व सैलाना के ग्राम शिवगढ़ के मध्य से कहीं भी उक्त रेल लाईन का संगम क्रॉसिंग होना प्रस्तावित है। इस परियोजना के लिये भूअर्जन का कार्य होकर बड़ी भूमि अधिग्रहित हो चुकी है।

संभव है इस राजमार्ग परियोजना के निर्माण की जानकारी राजमार्ग प्राधिकरण के प्रकाश में नहीं आई हो। किन्तु उक्त रेल परियोजना का राजमार्ग के निर्माण की अवधि के दौरान ही उस संभावित रेल लाइन क्रॉसिंग का ध्यान रखना आवश्यक है। अतः इस प्रस्तावित रेल लाईन के ऊपर से ब्रिज का प्रावधान करते हुए डबल लाईन की रेल मार्ग के निकल जाने का प्रावधान अभी से करना होगा। आने वाले समय में निकट भविष्य में ही जब यह रेल मार्ग का निर्माण कार्य तीव्र गति से प्रारंभ होगा, तब इस हाईवे के क्रॉसिंग करने में आवागमन में किसी भी प्रकार का बाधा या गतिरोध उत्पन्न न हो और अतिरिक्त धनराशी की व्यवस्था करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। अन्यथा तत्समय पुलिया बनाने की अवधि में एक्सप्रेस मार्ग के आवागमन में बाधा भी उत्पन्न होगी।

आशा है सभी संबंध में इस संबंध में ध्यान देते हुए अपने अपने स्तर पर उचित प्रावधान करने का प्रबंध करेंगे

भवदीय



(अनिल झालानी)

प्रतिलिपि -

1. श्रीमान मंडल रेल प्रबंधक महोदय, पश्चिम रेलवे, रतलाम
2. श्रीमान जिलाधीश महोदय, कलेक्टर कार्यालय, रतलाम
3. श्रीमान क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ई-2/ 167 अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास भोपाल(म.प्र.)
4. श्रीमान प्रबंधक महोदय, क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्लॉट नंबर 2 (नायर का मकान) प्रतापनगर एक्सटेशन, महु रोड रतलाम

Chaitanya Projects Consultancy Pvt. Ltd.

(An ISO 9001:2008 Certified Company)

(Architecture & Urban Planning, Highways & Bridges,
Survey & Geotech Investigation, GIS Application)

CIN NO. U74140DL2004PTC124286

Head Office:

C-5, 2nd Floor, R.K. Tower,
Plot No.- 21-22, Sector-4, Vaishali,
Ghaziabad, U.P.-201012, (India)

Phone : +91-120-4120472, 4110472

Email : chaitanya.projects@gmail.com

Website : www.chaitanyaprojects.com

प्रति,

परियोजना निदेशक,

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,

रतलाम, मध्य प्रदेश- 457001

टेलीफोन- 07412-297292

Email- ratlamnhai@gmail.com

क्रमांक- सीपीसी/एच.ओ./पी-151-म.प्र./2020-21/369/ 1251

दिनांक- 13.10.2020

विषय: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 148-एन के दिल्ली- वडोदरा 8 लेन से गुजरने वाली प्रस्तावित "रतलाम-बांसवाड़ा- डुंगरपुर रेल लाइन" क्रॉसिंग (स्थल संगम) पर ओवर ब्रिज का प्रावधान के संबंध।

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक भारत-रा.प्रा./प.का.ई.-रतलाम/2020/1877 दिनांक 12-10-2020.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि वर्तमान में निर्मित हो रहे मुंबई-दिल्ली एक्सप्रेसवे हाइवे पर रतलाम जिले के ग्राम पलसोड़ी व सैलाना के ग्राम शिवगढ़ के मध्य में उक्त रेल लाइन का संकरण (crossing) होना प्रस्तावित है जो कि हमारे संरक्षण के श्रृंखला-माप 173+600 से 173+700 के बीच में आ रही है।

उक्त तारतम्य में लेख है कि प्रस्तावित रेल लाइन के उपर से ब्रिज का प्रावधान पहले ही हमारे डीपीआर में किया गया है, जिसकी जी. ए. डी. उत्तर पश्चिम रेलवे, प्रधान कार्यालय, जगतपुर बाईपास, जवाहर सिकिल के पास, जयपुर के पत्र क्रमांक न- HQ/W/420/2/69(Vol-I) दिनांक 02-12-2019 के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई है। (प्रति संलग्न)

हम आपको हमारी सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए आश्वस्त करते हैं।

आपका आभारी

कृते चैतन्या प्रोजेक्ट्स कंसल्टेंसी पी.वी.टी. एन.टी.डी.

(एस. के. सिन्हा)

प्रबंध निदेशक





भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)



भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर
BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

परियोजना कार्यान्वयन इकाई/Project Implementation Unit

ऑफिस: बंगला नं. 2, प्रताप नगर एक्सटेंशन, रतलाम (म.प्र.) पिन-457001. टेलीफोन: 07412-297292
Office: Bunglow No. 2, Pratap Nagar Extn., Ratlam (M.P.) Pin - 457001. Tel: 07412-297292
e-mail: ratlamnhai@gmail.com, piuratlam@nhai.org

भाराराप्रा/पकाई/रतलाम/सृजन भारत/1883

दिनांक: 13/10/2020

प्रति,

सृजन भारत
श्री अनिल झालानी (संयोजक)
101, "देवप्रस्थ" पावर हाऊस रोड,
जिला-रतलाम (म.प्र.) 457001

विषय: दिल्ली से मुंबई के लिए बनने जा रहे 8 लेन मार्ग में से गुजरने वाली प्रस्तावित 'रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल लाइन' क्रॉसिंग (लसंगम स्थ) पर ओवर ब्रिज का प्रावधान रखने के संबंध में।

संदर्भ: 1. आपका पत्र दिनांक 29.09.2020।
2. डी.पी.आर. कंसलटेन्ट, मेसर्स चेतन्य प्रोजेक्ट्स कंसलटेन्सी प्रा.लि., का पत्र क्र.1251 दिनांक 13.10.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, वर्तमान में निर्मित हो रहे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-148एन के दिल्ली-वड़ोदरा एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रभावित जिला रतलाम ग्रामीण के ग्राम पलसोडी व सैलाना के ग्राम शिवगढ के मध्य में उक्त रेल लाईन का संकरण (Crossing) होना प्रस्तावित है। जिसका संरेखण के श्रृंखला-माप 173+600 से 173+700 के बीच में आ रही है।

उक्त के संबंध में यह भी अवगत कराना है कि, प्रस्तावित रेल लाइन के ऊपर से ब्रिज का प्रावधान पूर्व में ही डी.पी.आर. कंसलटेन्ट द्वारा कर दिया गया है, जिसकी जी.ए.डी. उत्तर पश्चिम रेलवे, प्रधान कार्यालय, जयपुर द्वारा पत्र के माध्यम से स्वीकृती प्रदान की जा चुकी है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

13.10.20
(रवीन्द्र गुप्ता)
परियोजना

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय अधिकारी-म.प्र., भाराराप्रा, क्षे.का., भोपाल (म.प्र.) को सूचनार्थ प्रेषित।